an>

Title: Need to release land for depiction of historical movements at Ponda, Goa.

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): The Ponda town has geographical advantage and located at the centre of State of Goa and falls in my South Goa Constituency. The erstwhile Portuguese Government had handed over a piece of land measuring 6500 Sq. mtrs. at Ponda to the Portuguese Military. Upon liberation of Goa, the said land was taken over by the Indian Army and that the same continues to be in the possession of the Indian Army. After various attempts, a part of the said land measuring 2530 Sq. mts. was released by the Indian Army, whereupon a Martyrs' Memorial has been constructed. For refurbishing the said memorial, known as Kranti Maidan, there is a proposal of Ponda Municipal Council for depiction of historical movements that led to liberation of Goa. Keeping this objective in mind repeated efforts have been made for release of remaining position of land.

I, therefore, strongly urge upon the Government to intervene and hand over the remaining portion of land to the Ponda Municipal Council.

*15

Title: Need to set up adequate facilities for storage of foodgrains in the country.

SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Between 2005 and 2013, FCI has admitted that more than 1,94,502 metric tonnes of foodgrains worth several crores have been wasted in the country due to several reasons. According to the data available, the damaged stock which stood at 95,075 MT in 2005-06 came down to 3,148 MT in 2012-13. The wastage was at 25,353 MT in 2006-07, 4,426 MT in 2007-08, and 20,114 MT in 2008- 09. Further it states that of the damaged stock, around 84 per cent (1,63,576 MT) was rice and 14 per cent wheat (26,543 MT). When so many people are dying due to hunger, so much of foodgrain is getting wasted. Even though the authorities may claim that the wastage is due to natural calamities like cyclone and floods, the real reason is inadequate storage facilities, pilferage, transit loss and negligence of the contractors like in Gujarat which attracted the strictures passed by the Gujarat High Court.

According to the United Nation's hunger report, India had the highest number of hungry people in the world estimated at 194 million. FCI's Central pool is having 568.34 lakh tonnes of foodgrains. Anticipating the poor monsoon predicted, the Central Government should take immediate steps for storage of foodgrains, increase FDI in all sectors with a stipulation to enhance percentage of investment in cold storage and encourage food processing industries. The Government should release excess foodgrains under PDS to the poor people through the States at concessional cost.

*t16

Title: Need to provide funds for rejuvenation of lakes and Ayad river in Udaipur, Rajasthan.

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर (राजस्थान) पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विश्व के मानचित्र पर अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उदयपुर शहर अरावली पर्वत मालाओं के मध्य स्थित चारों तरफ पानी की झीलों के मध्य बसा हुआ है। लगभग 5 लाख की आबादी वाला यह शहर, राजाओं के पुराने महल, बावड़ियाँ आदि स्थित हैं।

शहर के एक तरफ पिछोला झील, फतह सागर झील एवं पूर्वी भाग में उदय सागर झील बनी हुई है। फतह सागर से निकलने वाला पानी आयड़ नदी, जो हड़प्पा के काल से निकली हुई नदी है, उक्त नदी का पानी उदय सागर झील में जाता है तथा शहर का सीवरेज का पानी भी इसी नदी में जाता है जिससे पर्यावरण एवं जल प्रदूषित हो रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि झील संरक्षण एवं आयड़ नदी के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

*t17

Title: Need to set up the proposed AIIMS like Institute at Deogarh, Jharkhand.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar (Jharkhand) is one of the centre points of Santhal Pargana region and the entire Santhal Pargana region is backward and poor. This area does not have any medical facilities at all and needless to say the reduction on public health spending and the growing inequalities in health and health care are taking their toll on the marginalized and socially disadvantaged population of Santhal Pargana. This area is prone to malnutrition, with an estimated 75 per cent of children and mothers being anaemic. The children born in the tribal belt are one and a half time more likely to die before the fifth birthday and children below three years of age in scheduled tribes and scheduled castes are twice as likely to be malnourished than children in other groups. A tribal woman is one and a half time more likely to suffer the consequences of chronic malnutrition as compared to women from other social categories.

My insistence for setting up the AIIMS like institute at Deoghar is mainly on account of the suitable geographical location and ease of commuting for the patients from neighbouring towns like -Dumka, Godda etc. Deoghar is on the Kolkata â€" Patna main rail route and also connected with three National Highways. There is also 200 acres of land available at the place.

I humbly request that the proposed AIIMS like institute in Jharkhand be set up at Deoghar.

*t18

Title: Need to provide Scheduled Caste Certificate to all the eligible persons belonging to Bengali community living in Maharashtra.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महाराष्ट्र राज्य में मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर (महाराष्ट्र) लगभग 720 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है जो संभवतः देश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग एक लाख से अधिक बंगाली समाज वर्ष 1962 अर्थात विगत 52 वर्षों से पुनर्वास के तौर पर रह रहे हैं। सरकार ने बंगाली समाज को भूमि, मकान और आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं लेकिन उनको जाति के प्रमाण-पत्र की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

मेरे नक्सल प्रभावित सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले गरीब बंगाली समाज को जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से सरकार की दूसरी अन्य सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लाभ उठाने से यह समाज वंचित है।

मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि बंगाली समाज को पश्चिम बंगाल, कोलकाता, असम, ओड़िसा और निकट के राज्य छत्तीसगढ़ में " नमो शूद्र " यानि अनुसूचित जाति के रूप में जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है लेकिन महाराष्ट्र राज्य में बंगाली समाज को यह सुविधा अब तक नहीं मिल पायी है।

इस बारे में बंगाली समाज संगठन की ओर से कई बार शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से आंदोलन, धरना-प्रदर्शन एवं अनशन आयोजित किए जा चुके हैं और वे अपनी मांग के बारे में सरकार को पत्र-व्यवहार भी कर चुके हैं। उनकी मांग के बारे में जन-प्रतिनिधियों ने भी महाराष्ट्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है तथा केन्द्र सरकार से भी कई बार पत्र-व्यवहार हुआ है लेकिन, फिर भी आज तक बंगाली समाज को जाति का प्रमाण-पत्र नहीं मिल सका है जिस कारण बंगाली समाज में घोर असंतोष फैला हुआ है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर विषय की ओर ध्यान देकर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करके बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिलाए जाने की सुविधा प्रदान की जाए। यह मेरी प्रार्थना है।

*t19

Title: Need to formulate a comprehensive plan for proper conservation and protection of flora and fauna in Sita Mata wildlife sanctuary in Rajasthan.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ की सीमा पर सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। धार्मिक पृष्ठभूमि वाले इस अभ्यारण्य का इतिहास रामायण कालीन रहा है। माता सीता के वनवास का साक्षी सीता माता अभ्यारण्य प्राकृतिक संपदा से भी परिपूर्ण है। पौराणिक अवशेष के रूप में इस अभ्यारण्य में भागी बावड़ी, बाल्मिकी आश्रम, लवकुश के पद चिन्ह, हनुमान वाणी आदि हैं। अभ्यारण्य में अभी भी कई स्थानों पर पुराने अवशेष दिखाई देते हैं। यह अभ्यारण्य 429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विभिन्न प्रकार की दुर्लभ जड़ी-बूटियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहां पर 12 बीघा में फैला हुआ एक वट वृक्ष भी आकर्षण का केन्द्र है। सीता माता अभ्यारण्य में कैंसर के उपचार के लिए हस्ती पलाश एक पौधा भी पाया जाता है जिसके पत्तों के रस के सेवन से कैंसर रोगी को राहत मिलती है। प्राकृतिक दुर्लभ संयोग के रूप में ठण्डे एवं गर्म पानी का एक नाला भी समान रूप से बहता है। सीता माता अभ्यारण्य प्राकृतिक संपदा से भरा होने के साथ ही अपने आप में प्रकृति के कई दुर्लभ रूप समेटे हुए हैं। विश्व में अमेरिका के बाद केवल यहां पर इसी अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है जो अपने आप में विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। अभ्यारण्य में सभी प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं।

अतः सीता माता अभ्यारण्य के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वन एवं पर्यावरण तथा पर्यटन मंत्री से मांग करता हूं कि पौराणिक महत्व के सीता माता अभ्यारण्य के लिए विशेष सहायता एवं विकास की एक योजना तैयार कर दुर्लभ जीव-जन्तुओं एवं प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने का निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि ऐतिहासिक अवशेषों का संरक्षण हो। वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रयास हो। साथ ही वन क्षेत्र के विस्तार के लिए वृहद स्तर के वृक्षारोपण की योजनाएं बनाने की मांग करता हूं।

*t20

Title: Need to provide subsidy to farmers of Sikar district of Rajasthan for transportation of organic agricultural produces to distant markets.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र विशेषकर सीकर जिले में बड़ी मात्रा में जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन हो रहा है। स्थानीय स्तर पर इन उत्पादों के बहुत कम खरीददार हैं एवं साथ ही किसानों को अपने जैविक कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है। किसान अपने कृषि उत्पादों को बाहर अन्य क्षेत्रों में नहीं भेज पाता। इसका मुख्य कारण परिवहन लागत का अधिक होना है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शेखावटी क्षेत्र में उत्पादित हो रहे जैविक कृषि उत्पादों को देश के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए परिवहन सब्सिडी दी जाए ताकि आम लोग भी इन जैविक कृषि उत्पादों को प्राप्त कर सकें। इससे न सिर्फ किसानों को अपने कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा अपितु जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा।

*t21

Title: Need to introduce a new rail service between Surat and Varanasi and also take measures for improvement of existing rail services between the

two cities.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : सूरत और वाराणसी दोनों औद्योगिक नगरी हैं। दोंनों शहरों का बहुत ही पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा है। दोनों शहरों का आपसी व्यापारिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। सूरत की जरी और वाराणसी की साड़ियों का व्यापार एक-दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। इसकी वजह से दोनों शहरों के व्यापारियों का सूरत और वाराणसी के बीच प्रायः आना-जाना लगा रहता है।

इसके साथ ही साथ वाराणसी और उसके आस-पास स्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग सूरत में रोजगार के लिए आकर बस गए हैं और सूरत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे प्रवासी उत्तर भारतीयों का अपने गांव आना-जाना लगा रहता है जिनकी संख्या गर्मी की छुट्टियों के समय काफी बढ़ जाती है। गाड़ियों की कमी की वजह से इन यात्रियों की दुःखद यात्रा का वर्णन करना काफी कठिन है।

इस संबंध में समय-समय पर पूर्व में कई बार रेल मंत्रालय के अधिकारियों और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र के माध्यम से कई सांसदों और समाजसेवी संस्थाओं ने अलग-अलग सूचित करते हुए अनुरोध किया था कि इस मार्ग पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए और एक दुरंतों जैसी नई गाड़ी चलाई जाए जिससे इस मार्ग के यात्रियों को भी एक बेहतर रेल सुविधा का लाभ मिल सके।

वाराणसी संसदीय क्षेत्र को आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। वाराणसी शहर एक धार्मिक स्थल और आध्यात्मिक नगरी भी है। सूरत सहित गुजरात के अधिकांश लोग प्रायः वाराणसी की धार्मिक यात्रा करते हैं। ऐसे में वाराणसी और उसके आस-पास के मूल निवासियों, सूरत तथा वाराणसी के व्यापारियों और धर्मपरायण नागरिकों को सूरत से वाराणसी तक सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि सूरत वाराणसी के बीच नई रेल सेवा प्रारंभ करने के साथ ही साथ इस रूट की वर्तमान रेल सुविधाओं में सुधार करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

*t22

Title: Need to modernize railway stations in Bangalore Rural Parliamentary Constituency, Karnataka.

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): I would like to draw the attention of the Union Government towards the modernization of railway station in my Bangalore rural Parliamentary Constituency. During railway budget, it was announced that all the important railway stations in India would be modernized. However, after making the announcement, no steps have been taken to modernize the railway station. Bangalore is a global city. Lakhs of communters use the city railway station on a daily basis. The upgradation of Bangalore city railway station is long pending and overdue. The need for an international standard railway station is becoming extremely important.

I would like to bring to the notice of the Hon'ble Railway minister that in my Bangalore Rural parliamentary constituency, Yeshwanthapura, Aneka, Bidadi, Ramnagara and Channapatna railway stations also need to be modernized. Unless these railway stations are modernized, the vision of the Union Government to provide "Quality of life in Journeys" will remain just on paper.

*t23

Title: Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Viluppuram district, Tamil Nadu.

SHRI S. RAJENDRAN (VILUPPURAM): Vilupuram is the largest and one of the most backward districts in Tamil Nadu. It consists of 10 Revenue Taluks, 22 Panchayat Unions and 1490 revenue villages. Tamil Nadu Chief Minister successfully implemented Sakshar Bharathi Scheme". Chief Minister is taking innovative steps to make Tamil Nadu a 100% literate State in the country. Though there are State Government and Private Schools in my constituency, there is no Kendriya Vidyalaya in this region. Moreover, the Private Schools are charging exorbitant fees. Hence the lower and middle class people are unable to admit their children in the Private Schools. Also a number of Central Government employees are working in my constituency. They have no option but to admit their kids in the nearby districts. Therefore, I urge upon the Government to open a Kendriya Vidyalaya in Viluppuram, Tamil Nadu on top priority basis.

*t24

Title: Need to accord approval to the proposal of Government of Tamil Nadu for renovation of Kallani dam in the State.

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): The Grand Anaicut "Kallanai" built across River Cauvery over 2000 years ago is the living example of marvellous technology executed by Chola Dynasty in Tamil Nadu. Till today it irrigates ten thousands of acres of land in Thanjavur, Trichy, Nagapattinam and Thiruvarur Constituencies. Now, the Government of Tamil Nadu has submitted a Project report to the Central Water Commission for renovation of this historical anicut. The 1st Phase of Project includes extension, renovation and re-modelling of Grand Anicut Canal system costing Rs. 261 0.00 crores as announced by the Hon'ble state Chief Minister. If the first phase is completed more than 3 lakh acres of agricultural land will be brought under irrigation additionally in Thanjavur, Pudukottai and Tiruvarur districts. Therefore, on behalf of the farmers and Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, I

request the Government to approve the scheme immediately with full financial support for the first phase of this Project.

*t25

Title: Need to expedite installation and operation of Doppler Weather Radar in Paradip.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): The East Coast region along the Bay of Bengal in Odisha is a cyclone prone area. Every year during the period from May to November, this region, especially Jagatsinghpur, Kendrapara, Puri, Balasore and Ganjam districts faces the wrath of disasters resulting in loss of lives and property. Especially, after the 1999 super cyclone, the Government of India following the request of State Government initiated the installation of Doppler Weather Radar in different cyclone prone areas in Coastal Odisha in order to track/forecast the cyclone and measure the wind speed accurately so that timely precautionary measures could be taken. Paradip in my Parliamentary constituency is one of the places in the State, was selected for installation of the Doppler Weather Radar. In this regard, as per the instruction of a team of the Earth Sciences and Bharat Electronics Limited, the Doppler Weather Radar was installed in 2000 in Paradip. However, the same is yet to be functional.

In this regard, I urge upon the Minister of Home Affairs to look into the matter and expedite operation of the Doppler Weather Radar in Paradip, Odisha thereby ensuring effective and advance information about the cyclones which could subsequently save the lives and property.

*t26

Title: Need to undertake construction of breakwater structure to facilitate smooth passenger and vessel operations at Andrott Island, Lakshadweep.

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Andrott Island is the largest island among the Lakshadweep group of islands. The embarkation and disembarkation of passengers at Andrott is carried out at the northern side unlike other islands where there is eastern side shelter. Though the construction of second phase of breakwater structure is over the berthing facility inside, the shelter has not been completed. There is a total space of 223 meters which can be utilized for developing berths. Only 99 meters berth has been developed so far in two lengths of 55 meters and 40 meters. Lakshadweep Harbour Works may be requested to propose construction of three berths in the available space in addition to the existing.

I strongly urge upon the Government to take up this project in right earnest as it will definitely improve the facilities for the passenger and vessel operations to a large extent.

*t27

Title: Need to include Dhangar caste in the list of Scheduled Tribes.

SHRI RAJU SHETTY (HATKANANGLE): Dhangar caste of Maharashtra for their survival wander extensively in the hilly area. On the one hand, due to urbanization and extensive farming they have been banned in the hilly area. This has led to difficulties in the way of development of this community. Next generation of this community also suffers from lack of education, medical facility and unable to taste the fruits of development. Though the Government accept the fact that this community belongs to Scheduled Tribes like ORAN community, but has denied them this status. GOVERNMENT OF INDIA REPORT ON THE BACKWARD CLASSES COMMISSION VOL-II (LIST 1955 PAGE No. 66) clearly mentions the deep backwardness of this community. DESCRIPTIVE ETHNOLOGY OF BENGAL -1872- In this book on Page -215 the information regarding the Oran community (ST) is given and also mentioned about the similar community like DHANGAR who resides in the hill area and involved in animal management. There are many Government documents showing the status of Dhangar community. It is my humble request to the Government of India to include Dhangar Caste in the list of Scheduled Tribes.

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

HON. DEPUTY SPEAKER: Please go to your seats and speak from there.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You go there and raise whatever you want to raise.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow the 23rd July, 2015 at 11.00 a.m.

14.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, July 23, 2015 / Shravana 1, 1937 (Saka).

---

* Dद्वड्ढ द्यद्द हद्ददय्त्ददद्वद्दद्वद्म् त्दय्ड्ढद्धद्धद्वद्रय्त्द्दद्म् त्द ण्ड्ढ Hद्दद्वम्ड्ढ, य्ठ्ठद्धद्धड्ढड्ड द्दद्वड्ढद्य्त्द्दद्म् हद्दद्वथ्ड्ड दद्दद्य् डड्ढ य्ठ्ठत्ड्ढद द्वद्र ढद्दद्ध द्दद्धठ्ठथ् ठ्ठदर्ड्ढद्धद्म. ण्ड्ढद्धड्ढढद्दद्धड्ढ, ण्ड्ढम्ड्ढ य्ठ्ठद्धद्धड्ढड्ड द्दद्वड्ढद्य्त्द्दद्म् ड्र्ढद्धड्ढ य्द्धड्ढठ्ठय्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् द्वदय्ठ्ठद्धद्धड्ढड्ड द्दद्वड्ढद्य्त्द्दद्म्.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.